कोरोना प्रभावित अर्थव्यवस्था में जान फूँकता आत्मनिर्भर भारत अभियान : एक आर्थिक विश्लेषण

डॉ. असलम खॅान
सहा.प्राध्यापक (अर्थषास्त्र)
षासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय दमोह (म.प्र.)

परिचय

जैसाकि हम सभी जानते है कि सारा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है। इससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहा है। इस महामारी ने सारे विश्व को सोचने पर मजबूर कर दिया है। चूँकि हमारी अर्थव्यवस्था एक विकाससील अर्थव्यवस्था है। यहाँ की आबादी जनगणना 2011 के अनुसार 1210569573 है। [1] वर्तमान में लगभग 130 करोड़ है जो विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। इतनी आबादी की प्रति व्यक्ति आय (2017—18 में बाजार मूल्य के आधार पर) 114958 रू ने इसके संघर्ष की कहानी लिख दी है।[2] प्राचीनकाल से हमारी अर्थव्यवस्था अनेक समस्याओं से लड़ती आ रही है। वर्तमान कोरोना महामारी ने हमारी अर्थव्यवस्था को लगभग एक दशक के लिए पीछे कर दिया है। भारत में इस महामारी से लडने एवं इस पर जीतने के लिए सभी ने क्षमतानुसार प्रयास किया है एवं कर रहे हैं। यही कारण है कि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में कोरोना से प्रभावित होने वालों का प्रतिशत्, जनसंख्या के अनुपात में कम है। इससे लड़ने और जीतने के लिए सभी राज्यों की सरकारों ने अपने—अपने स्तर से कार्य योजनाये बनाईं हैं और उन पर अमल भी किया और कर रहे हैं। केन्द्र सरकार ने भी देश हित में एक ऐंसे अभियान की शुरूआत की जो कोरोना संकट में रामबाण सिद्ध हो रहा है। यह योजना या अभियान आत्मनिर्भर भारत अभियान है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदर मोदी जी ने 12 मई 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रारंभ किया है। इस अभियान का श्रीगणेश करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कोविड —19 महामारी से पहले तथा बाद की दुनिया के बारे में बात करते हुए कहा कि **''21 वीं सदी के भारत के सपने को साकार करने के लिये देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता (सेल्फ रिलाईंस) की परिभाषा में बदलाव आया है। आत्मनिर्भरता (सेल्फ रिलाईंस), आत्म—केंद्रित (सेल्फ सेन्टर्ड)अलग है।''** उन्होनें आगे कहा कि भारत **''वसुधैव कुटुंबकम''** की संकल्पना में विश्वास करता है। चूँकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है, अतः भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है। **'आत्मनिर्भर भारत'** के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाएगा अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी। संभवतः प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का श्रीगणेश कर कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था से लड़ने एवं जीतने की मंशा के साथ वासुदैव कुटुम्बकम की भावना को विश्व पटल पर सभी देशों को पुनः स्मरण कराया है, जैसा कि हमारे देश की सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक अतीत काल से बना हुआ है।

आत्मनिभर भारत अभियान मिशन के चरणः— इस अभियान को दो चरणों में लागू किया जाएगा। यथा प्रथम चरण में चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके एवं द्वितीय चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करे तो इनमें प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं— (1) कृषि प्रणाली (रीफार्मेंशन ऑफ एग्रीकल्चर सप्लाई चेन एंड सिस्टम) (2) सरल और स्पष्ट नियम कानून (3) उत्तम आधारिक संरचना (रीफार्मेशन ऑफ इन्फ्रास्टरक्चर) (4) समर्थ और संकल्पित मानवाधिकार (केपेबल ह्यूमन रिसोर्स) (5) बेहतर वित्तीय सेवा (6)नए व्यवसाय को प्रेरित करना (टू मोटिव न्यू बिजनैस) (7) निवेश को प्रेरित करना(प्रोवाईड गुड इनवेस्टमेंट अपारचुनैटीज)

आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्य :—

आपदा को अवसर में बदलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश को संबोधित करते हुए एक राहत पैकेज, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है कोविड—19 महामारी संकट से लड़ने में आत्मनिर्भर भारत अभियान निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा और एक आधुनिक भारत की पहचान बनेगा। 12 मई 2020 को, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कड़ी प्रतिस्पर्धा के खिलाफ स्वतंत्र बनाने के उद्देश्य से 20 लाख करोड़ रुपये (भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत् के बराबर) के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। गरीबों, मजदूरों, प्रवासियों को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए जो कोविड 19 से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। इस

Copyright @ 2020 Authors

घोषणा के बाद, वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने लगभग पाँच प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आर्थिक पैकेज के तहत विस्तृत उपायों की घोषणा की।

आत्मनिर्भर भारत अभियान की संरचना का विष्लेषण करना यहाँ आवश्यक है। इस अभियान के पाँच स्तंभ हैं, जिनपर यह अभियान केंद्रित है जो इस प्रकार हैः—ः

(1) **अर्थव्यवस्था (इकॉनोमी):** —जो वृद्धिशील परिवर्तन (इनक्रीमेंटल चैंज) के स्थान पर बड़ी उछाल (क्वॉनटम जम्प) पर आधारित होगा।

(2) **अवसंरचना (इनफ्रास्ट्रक्चर):**—ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बनेगा।

(3) **प्रौद्योगिकी (इकोलॉजी):** — 21 वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणालीय होगी।

(4) **गतिशील जनसांख्यिकी (वाइब्रेट डेमोग्राफी):** —जो आत्मनिर्भर भारत के लिये ऊर्जा का स्रोत होगा।

(5) **मांग (डिमांड):—** भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिये।

यदि हम इस अभियान का गहन अध्ययन करें तो यह पैकैज न केवल कोरोना प्रभावित अर्थव्यवस्था का उपचार कर विकास का द्योतक है बल्कि भविष्य में आने वाली आर्थिक चुनौतियों से लडने के लिए मददगार होगा। इस अभियान के प्रमुख उदेश्य निम्नलिखित हैः—

(1) यह अभियान हमारी अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योग एम.एस.एम.ई., मजदूरों, मध्यम वर्ग उद्योगों सहित विभिन्न वर्गो की जरूरतों को पूरा करेगा।

(2 यह अभियान भारत में स्थापित विभिन्न सेक्टरों में दक्षता बढ़ाते हुए गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेगा।

(3) वास्तव में यह पैकेज देश में संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के गरीबों, मजदूरों, प्रवासियों इत्यादि को सशक्त बनाने पर भी बल देगा।

(4) एक महत्वपूर्ण उदेश्य को लेकर यह अभियान चलेगा। अर्थात संकट के दौरान हमारी सभी जरूरतें स्थानीय स्तर पर यानी देश में ही पूरी होंगी, अर्थात लोकल फार वोकल के मंत्र से पुनः हमारी अर्थव्यवस्था में संचार लाया जायेगा।

(5) हम जानते हैं कि कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से करोड़ों मजदूर कार्यस्थल से अपने घरों को वापस लौटे हैं। इस अभियान में कार्यस्थल से लौटे मजदूरों को ग्रहनगर में ही रोजगार दिया जाने का मुख्य लक्ष्य है।

(6) आत्मनिर्भर भारत अभियान की यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस पैकेज के तहत मजदूरों को अलग—अलग क्षेत्र एवं स्थानों में रोजगार मिलेगा। इसके तहत 25 अलग—अलग योजनाओं को एक जगह समाहित कर एक प्लेटफार्म बनाया गया ताकि मजदूरों को इस महामारी के दौरान आयी बेरोजगारी में काम उपलब्ध कराया जा सके.।

(7) इस अभियान में इस बात का भी आह्वान है कि कोरोना प्रभावित अर्थव्यवस्था में बड़ती बेरोजगारी को हल करने के लिए बड़—बड़ी कंपनियों से एम.ओ.यू.साइन कराया जायेगा, जिसका मकसद प्रवासी मजदूरों को उनके जिले में ही अतिषीघ्र रोजगार उपलब्ध कराना होगा।

(8) इस योजना अथवा अभियान का उद्देश्य 130 करोड़ भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि देश का हर नागरिक कोरोना जैसे प्राकृतिक संकट की इस घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चल सके और कोविड—19 की महामारी को हराने में अपना योगदान दे सके। यह अभियान निश्चित रूप से देश को एक समृद्ध और संपन्न भारत के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभायेगा।

(9) भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसमें विभिन्न सेक्टर हैं। इस पैकेज से सभी सेक्टरों की दक्षता बढ़ेगी और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। इस योजना के जरिये देश की अर्थव्यवस्था को 20 लाख करोड़ रूपये का संबल मिलेगा।

(10) हम सभी लोग जानते है कि कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉक डाउन की स्थिति चल रही है जिसका सबसे ज्यादा बुरा असर देश के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों, श्रमिकों, मजदूरों और किसानो पर पड़ रहा है इन सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों, श्रमिकों, मजदूरों और किसानो को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया । इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा चुने गए पात्र सभी लाभार्थियों को सहायता राशि आर्थिक पैकेज के रूप प्रदान की जाएगी । केंद्र सरकार की इस मदद से भारत देश एक नई ऊँचाई की तरफ जायेगा।

(11) इन सबके अलावा आत्मनिर्भर योजना में समग्र सुधारों के अधूरे एजेंडे को भी शामिल किया गया है, जिसमें सिविल सेवाओं, शिक्षा, कौशल और श्रम आदि में सुधार शामिल हो सकते हैं। जिसके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से विकास के पथ पर दौड़ सकेगी।

इस अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल फार वोकल विचारधारा पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संकट के समय हमारी सभी आवश्यकताओं ने स्थानीय स्तर पर या लोकल स्तर पर यानी देश में ही पूरी हुई है। अर्थात लोकल

Copyright @ 2020 Authors

वोकल ने इस महामारी जैसे दौर में संचार फूँक रखा है। प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल मंत्र पर बल देते हुए कहा है कि ''अब लोकल उत्पादों का गर्व से प्रचार करने और इन लोकल उत्पादों को वैश्विक बनाने का वक्त आ गया है।'' इस अभियान को निम्न भागों में बांटा गया है।

प्रथम भाग या प्रथम किस्त में सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों के त्वरित विकास की पहल की गई जिसके अंतर्गत प्रमुख बिंदु निम्न रहेः–

(1) एम.एस.एम.ई. सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रू की आपातकालीन कार्यशील पूंजी की सुविधा होगी। इसमें व्यवसायिओं को राहत देने के लिए बकाया ऋण के 20 प्रतिशत् की अतिरिक्त कार्यशील पूंजी रियायती ब्याज दर पर सावधि ऋण (टर्म लोन) के तौर पर दी जायेगी । जिसकी समय सीमा 29 फरवरी 2020 तक रखी गयी है।

(2) एम.एस.एम.ई. फण्ड ऑफ फंड्स के माध्यम से 50000 करोड़ रू की इक्विटी को उपलब्ध कराया जायेगा। इसमें सरकार 10000 करोड़ के कोष के साथ एक फंड ऑफ फंडस की स्थापना करेगी जो कि एम.एस.एम.ई.को मदद करेगी।

(3) एम.एस.एम.ई.की एक नई परिभाषा अभियान के दौरान सामने आयी जो निम्न हैः–

सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के नए मानदण्ड

(मशीनों एवं प्लांट में निवेश/वार्षिक टर्न ओवर)

कमांक	केटेगरी	विनिर्माण और सेवा क्षेत्र (सर्विस सक्टर) के उद्यम
1	सूक्ष्म उद्यम	1 करोड़ रू से कम निवेश और 5 करोड़ रू से कम टर्न ओवर
2	लघु उद्यम	10 करोड़ रू से कम निवेश और 50 करोड़ रू से कम टर्न ओवर
3	मझोले उद्यम	50 करोड़ रू से कम निवेश और 250 करोड़ रू से कम टर्न ओवर

स्त्रोत :– प्रतियोगिता दर्पण जून–जुलाई 2020 आगरा पेज नं. 71

(4) इस अभियान में सरकार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट को 4000 करोड़ रू देकर उन्हें मदद करेगी।

(5) इस पैकेज में कर्ज के बोझ से दबे एम.एस.एम.ई के लिए 20000 करोड़ रू का अप्रधान ऋण या कर्ज का प्रावधान किया गया है।

(6) इस अभियान में एम.एस.एम.ई के लिए ई–मार्केट लिंकेज को बढ़ावा दिया जायेगा। जो व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के प्रतिस्थापक के रूप में कार्य करेगा।

(7) अभियान में सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमों में संशोधन का हवाला देकर कहा कि 200 करोड़ रू तक की सरकारी निविदाओं के लए कोई भी वैश्विक निविदा की आवष्यकता नहीं होगी।

(8) व्यवसायिक और संगठित श्रमिकों या कामगारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि की सहायता का भी उल्लेख अभियान में है। इसके तहत लगभग 2500 करोड़ रू का कुल लाभ 72.22 लाख कर्मचारियों को मिलेगा, जो कि काबिले तारीफ है।[3]

(9) इस अभियान में ई.पी.एफ. अंशदान को नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए 3 माह तक घटाया जाएगा। इससे प्रतिमाह लगभग 2250 करोड़ रू की तरलता मिलेगी।[4]

(10)इस अभियान के तहत् पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन और रूरल इलेट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (डिस्काम) के लिए इसमें 90000 करोड़ रू की तरलता सुलभ कराई जाएगी।

(11) इस पैकेज़ में रियल एस्टेट परियोजनाओं को राहत देते हुए उनकी पंजीकरण एवं पूर्णता तिथि 6 माह तक बढ़ाने का प्रावधान है। इसे राज्य सरकार 3 माह और अपनी स्थिति अनुसार बडा सकता है।

(12) एन.बी.एफ.सी./एच.एफ.सी./एम.एफ.आई. के लिए इस अभियान के अंतर्गत 30000 करोड़ रू की विशेष तरलता योजना एवं एन.बी.एफ.सी./एम.एफ.आई. की देनदारियों के लिए 45000 करोड़ रू की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 का भी जिक्र इस अभियान में है।

(13) पंजीकृत ठेकेदारों के लिए राहत देते हुए 6 माह का समय तथा व्यवसायिओं के लिए कर राहत की भी बात इस अभियान में की गई है।

(14) उपर्युक्त बिन्दुओं के अलावा कर संबंधी उपाय भी इस अभियान के अंतर्गत दिये गये। स्त्रोत पर कर कटौती और स्त्रोत पर संगृहीत कर की दरों में कटौती, जिसके अंतर्गत निवासियों को होने वाले सभी गैर–वेतनभोगी भुगतान के लिए टी.

 Copyright @ 2020 Authors

एड.एस. दरों और स्त्रोत पर संगृहीत कर की दर में वित्त वर्ष 2020–21 की शेष अवधि के लिए निर्दिष्ट दरों में 25 प्रतिशत् की कमी की जायेगी। इससे 50000 करोड़ रू की तरलता सुलभ होगी। [5]

इन सबके अलावा कई और प्रमुख मुद्दे हैं जो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कार्यरत हैं तथा आने वाले समया में क्रियान्वित किये जायेगें।

इस पैकेज की प्रथम किस्त की घोषणा के बाद प्रवासियों, किसानों, छोटे व्यवसाय और फेरी वालों के अलावा गरीबों की सहायता के लिए 15 मई 2020 **द्वितीय चरण** में निम्न बिन्दुओं की घोषणा की गईः–

(1) प्रावासियों के लिए 2 महीने (मई–जून 2020) के लिए प्रति महीने प्रति कामगार 5 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न और प्रति परिवार 1 किलोग्राम चना का मुफ्त आवंटन किया जायेगा। इस पर सभावित व्यय लगभग 3500 करोड. रू के व्यय का वहन भारत सरकार करेगी।

(2) अगस्त 2020 तक देश में पी.डी.एस. सिस्टम में राशन कार्डो की पोर्टेबिलिटी की पायलट योजना को 23 राज्यों में लागू करने का प्रावधान है। जिससे देश का कोई भी नागरिक राशन कार्ड होने पर कहीं से भी राशन ले सकेगा। अर्थात एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का संचालन होगा।

(3) देश के प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए सस्ते एवं सुलभ किराये के मकान उपलब्ध कराने की योजना शुरू की जायेगी। जिससे कोई भी श्रमिक बेघर नही रह सकेगा।

कर्जीले उद्यमी अर्थात शिशु मुद्रा ऋण लेने वालों को एक साल के लिए 2 प्रतिशत् ब्याज की छूट के लिए 1500 करोड़ रू की राहत राशि जारी होगी।

(4)पैकेज में पी.एम.ए.वाई. (शहरी) के तहत एम.आई.जी. के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के विस्तार के माध्यम से आवासन क्षेत्र और मध्यम आय समूह को 70000 करोड़ रू की राशि का प्रावधान है।

(5)आत्म निर्भर भारत अभियान में स्ट्रीट वेंडरों को ऋण के लिए 5000 करोड़ रू की राशि का प्रावधान है।

(6)क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के द्वारा 6000 करोड़ रू के निधियों के रोजपरक एवं प्रकृतिअनुकूल कार्य कराने का प्रावधान है, इसमें वन संपदा पर आधारित कार्य, वन्य जीव संरक्षण संबधी बुनियादी सुविधाओं के विकास आदि क्षेत्र शामिल है। इससे श्रमिकों रोजगार मिलेगा।

(7)भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि कही जाती है। पैकेज में इसको भी ध्यान में रखा गया है। नाबार्ड के माध्यम से किसानों की मदद के लिए 30000 करोड़ रू की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी का भी प्रावधान है। इसके अलावा इनकों किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रू का ऋण प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज की आवश्यकतानुसार **तृतीय किस्त** भी सरकार ने जारी की जिसके अंतर्गत कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण सेक्टरों के लिए कृषि अवसंरचना लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने, क्षमता निर्माण, गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों आदि पर विशेष बल दिया गया है। इस किस्त के प्रमुख बिन्दु निम्न हैंः–

(1) कृषकों के लिए फार्म गेट या कृषि द्वार पर केन्द्रित एक लाख करोड़ का कृषि आधारभूत ढॉचा के लिए एक कोष बनाया जायेगा, जो कृषकों को राहत प्रदान करेगा।

(2) सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों (एम.एफ.ई.)के औपचारिकरण या उत्थान के लिए 10000 करोड़ की योजना की घोंषणा की गई।

(3) मत्स्य पालन को बढावा देने के लिए भी इस पैकेज में प्रावधान है। इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस. वाई.) के माध्यम से मछुआरों के लिए मत्स्यपालन से संबंधित गतिविधियों के लिए 20000 करोड़ रू राशि का प्रावधान रखा गया है।

(4) पशुपालन के विकास लिए पशुपालन बुनियादी ढँाचा विकास कोष स्थापित किया जायेगा। जिसके अंतर्गत 15000 करोड़ रू राशि का प्रावधान है। इसके अलावा पशुओं के कल्याण के लिए राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम के भी श्री गणेश की चर्चा की गयी। इसके अंतर्गत खुरपका, मुहपका रोग (एफ.एम.डी.) और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को शामिल करते हुए इसमें 13343 करोड रू का प्रावधान किया गया है।

(5) सब्जियों की खेती करने वाले कृषकों को भी ध्यान रखा गया । टमाटर, प्याज, और आलू (टॉप) से इनका विस्तार सभी सब्जियों (टोटल) तक करने के लिए पैकेज में 500 करोड़ रू की राशि का प्रावधान रखा गया है। जो कि सब्जी की खेती करने वाले कृषकों के लिए लाभदायक होगा।

(6) ऐंसे कृषक जो औषधीय या हर्बल खेती करते हैं , को पैकेज में 4000 करोड़ रू का परिव्यय प्रस्तावित किया है।

(7) पैकेज में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देने के लिए 500 करोड़ राशि का भी जिक्र गया है।

 Copyright @ 2020 Authors

(8) उपर्युक्त बिन्दुओं के अलावा कृषकों को अपनी फसल का उचित दाम मिल सके इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियग में संशोधन का , कृषकों की फसलों के विपणन का विकल्प प्रदान करने के लिए कानून लाने की भी चर्चा की है। इसके साथ–साथ कृषकों की उपजों का मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता का भी आश्वासन दिया गया है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान की **चौथी किस्त** में भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अनेक बिन्दुओं को शामिल किया गया जिनमें प्रमुख निम्न है:–

(1) निवेश क्षेत्र में सुधार के लिए अनेक प्रावधान किये गए इसमें जल्दी निवेश स्वीकृति, निवेशक एवं केन्द्र/राज्य सरकार को जोड़ने के लिए परियोजना विकास इकाई की स्थापना, निवेश को आकर्षित करने के लिए निवेश रैकिंग तैयार करने, नए चैम्पियन(अग्रणी)क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने हेतु सोलर पीवी निर्माण, उन्नत सेल बैटरी स्टोरेज आदि क्षेत्रों के प्रोत्साहन एवं विकास के लिए योजनाओं का शुभारंभ अतिशीघ्र होगा।

(2) इस पैकेज में 8 क्षेत्रों कोयला, रक्षा उत्पादन, खनिज, बिजली क्षेत्र, नागरिक उड्डयन, सामाजिक आधारभूत ढाँचे एवं अंतरिक्ष और परमाणु उर्जा को बहुत महत्व दिया है।

(3) कोयला क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की पेशकश, कोयला क्षेत्र में खनन, उत्खनन सभी में उदार व्यवस्था लागू करना, कोयला क्षेत्र में राजस्व एवं रोजगार के विविध अवसर, आदि पर विशेष जोर दिया जायेगा।

(4) रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना , रक्षा सामग्री के उत्पादन में नीतिगत सुधार करना इसमें प्रस्तावित है।

(5) नागरिक उड्डयन के लिए कुशल एवं अच्छे एयरस्पेस का प्रबंधन, पी.पी.पी. के माध्यम से अधिक विश्वस्तरीय हवाई अडड़े आदि को विकसित करना, विमान के रखरखाव , मरम्मत और जीर्णोद्वार (एम.आर.ओ.) के लिए भारत को विश्व का वैश्विक बनाने जैसे बिन्दुओं को समाहित किया गया है।

(6) खनिज क्षेत्र को बढ़ावा देने लिए इस पैकेज में निजी निवेश को बढ़ावा के साथ–साथ खनिज क्षेत्र में नीतिगत सुधार करने पर विशेष बल दिया गया।

(7) इस पैकेज में विद्युत क्षेत्र में सुधार करने की भी चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत टैरिफ सम्बंधी नीति में सुधार, बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण एवं विद्युत उत्पादन एवं उद्योग को बढ़ावा देने, केन्द्रशासित प्रदेशों में विद्युत वितरण का निजीकरण आदि के द्वारा विद्युत क्षेत्र में सराहनीय पहल की पेशकश भी इस पैकेज में है।

(8) सामाजिक अवसंरचना किसी अर्थव्यवस्था का मत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। इस पैकेज में संशोधित व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 8100 करोड़ रू को केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों /वैधानिक संस्थाओं द्वारा परियोजनाओं के विकास में प्रस्तावित किया गया है।

(9) परमाणु ऊर्जा से संबंधित सुधार कार्यक्रमों की चर्चा इस पैकेज में की गई। कैंसर और अन्य बीमारियों के उपचार हेतु चिकित्सा आइसोटोपा के उत्पादन के लिए पी.पी.पी. मोड में अनुसंधान रियक्टर की स्थापना की भी चर्चा की गई।

(10) अंतरिक्ष क्षेत्र में गतिविधियों को बढ़ाने ,निजी भागीदारी बढ़ाने एवं इसरो की सुविधाओं में इजाफा करने की भी अनुशंसा इस पैकेज में की गई है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अगली अर्थात **पांचवी किस्त** में देश के सात सेक्टर्स में सरकारी सुधारों और सहायक उपायों के संबंध में घोषणा की गई है।

(1)इस पैकेज में भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा के आवंटन में 40000 करोड़ की वृद्वि होगी। इस प्रकार वर्ष 2020–21 के लिए मनरेगा के लिए कुल आवंटन 101500 करोड़ रू हो गया। [6]

(2) स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों की सख्या में वृद्वि करने, सभी स्वास्थ्य केंद्रों में महामारियों से बचने के प्रबंध की विशेष सुविधा करने, आई.सी.एम.आर द्वारा स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय संस्थागत प्लेटफार्म बनाकर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने, आदि की विशेष चर्चा की है।

(3) कोविड–19 से लड़ने एवं इससे जीतने के लिए कोविड के बाद समानता के साथ प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को महत्व देना इस अभयान का एक बिन्दु रहा है। इसके के लिए पी.एम. ई–विद्या डिजीटल/आनलाईन बहु माध्यम शिक्षा पद्वति , विभिन्न प्रकार के शिक्षा प्लेटफार्म जैसे स्वयं (एस.डब्ल्यू.ए.एम.) , दीक्षा आदि के माध्यम से अध्ययन अध्यापन कराना, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए मनोदर्पण कार्यक्रम आदि कराने के विशेष प्रावधान इस पैकेज में किये गए। जो कहीं न कहीं कोविड से प्रभावित देश की शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए मील के पत्थर साबित होगें।

(4)इस पैकेज में कम्पनी अधिनियम के तहत् की गई गलती मिस्टेक या चूक को अपराध की श्रेणी से बाहर करने एवं दिवालिया एवं शोधन अक्षमता संहिता (आई.बी.सी.) से संबंधित उपायों के माध्यम से कारोबार में सुगमता सहजता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को और अधिक बेहतर करने एवं नए आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति में संषोधन की भी बात की गई है।

 Copyright @ 2020 Authors

इन सबके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से केन्द्र सरकार लगभग सभी राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता के साथ–साथ विभिन्न प्रकार की सहायता की और कर रही है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान की चुनौतियां:–

आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित चुनौतियों की चर्चा करना लाज़मी है। हाल ही में, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज और बिग–बैंग सिस्टमिक सुधारों की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य दो गुना है। सबसे पहले, तरलता जलसेक और गरीबों के लिए सीधे नकद हस्तांतरण जैसे अंतरिम उपाय तीव्र तनाव वाले लोगों के लिए सदमे अवशोषक के रूप में काम करेंगे।

देश में इस अभियान के तहत् विकास के गंभीर क्षेत्रों एवं दीर्घकालिक सुधार जो विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और आकर्षक हैं बनाने के साथ–साथ कोविड –19 महामारी से प्रभावित आर्थिक गतिविधि को पुनर्जीवित कर सकते हैं और कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), बिजली, कोयला और खनन, रक्षा और विमानन आदि जैसे क्षेत्रों में विकास के नए अवसर पैदा कर सकते हैं, हालाँकि इस योजना की दूरदर्शिता को पूरा करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जिनमें प्रमुख निम्न हैं:–

(1) इस पैकेज के माध्यम से कर्जमाफी, मुफत का राषन एवं मषीनीकरण से अर्थव्यवस्था में अनियिमित उत्पादन की संभावना भी बन सकती है जो देष को मंदी व बेरोजगारी के चक्रव्यूह में फंसा सकते हैं।

(2)अन्य चुनौतियों के संबध में हम चर्चा करे तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि तरलता से संबंधित मुद्दे अर्थात 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में राजकोषीय और मौद्रिक दोनों उपायों का समावेश होता है, जो बाद में क्रेडिट गारंटी और तरलता की प्रकृति के कारण बैंकों और अन्य वित्तीय क्षेत्र के संस्थानों में प्रति अर्थव्यवस्था के बजाय शामिल है।

(3) इस पैकेज का अधिकांश भाग तरलता उपाय वाला है जो भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों द्वारा नागरिकों को प्रेषित किया जाना चाहिए। इससे यह प्रसारण मौद्रिक नीति के अक्षम संचरण के कारण सुचारू नहीं होने की संभावना अधिक है।

(4) मांग की कमी भी एक कारक है। लॉकडाउन ने कुल मांग को कम कर दिया है, और एक राजकोषीय प्रोत्साहन की जरूरत है। हालांकि, पैकेज, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट इन्फ्यूजन पर अत्यधिक निर्भरता से, यह पहचानने में विफल रहा है कि निवेश तभी उठाएगा जब आम वर्ग के लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा हो।

(5) पिछड़े और अग्रगामी संबंधों की कमी का बिन्दु भी महत्वपूर्ण है। जब तक बाकी घरेलू अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित नहीं किया जाता, एमएसएमई क्षेत्र को मांग में कमी का सामना करना पड़ सकता है, और इसका उत्पादन जल्द ही बंद होने की संभावना अधिक है।

(6)राजकोषीय घाटा भी एक चिंतनीय विषय है। सरकार का दावा है कि प्रोत्साहन पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत् है। हालांकि, इसका वित्तपोषण करना मुश्किल होगा क्योंकि सरकार राजकोषीय घाटे को लेकर चिंतित है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान या पैकेज का प्रभाव

(अ) प्राथमिक क्षेत्र:– कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए घोषित उपायों (ईसीए, एपीएमसी, अनुबंध निर्धारण, आदि में संशोधन करने के लिए सुधार) विशेष रूप से परिवर्तनकारी हैं, ये सुधार निम्न हैं:–

(1) वन नेशन वन मार्केट उद्देश्य की दिशा में कदम हैं और भारत को दुनिया का खाद्य कारखाना बनने में मदद करते हैं।

(2) ये अंत में एक स्व–स्थायी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे।

(3) इसके अलावा, 40,000 करोड़ रुपये के मनरेगा फंड जा श्रमिकों को उनके गांवों में लौटने पर मजदूरी के संकट को कम करने में मदद कर सकते हैं।

(ब) द्वितीयक क्षेत्र:– भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एम.एस.एम.ई.एस.के महत्व को देखते हुए, पैकेज के तहत एम.एस.एम.ई.एस. के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के जमानत–मुक्त ऋण की सुविधा इस वित्त–प्रधान क्षेत्र में मदद करेगी और इस तरह अर्थव्यवस्था की निराशाजनक स्थिति को कम कर देगी। इस क्षेत्र के प्रमुख बिन्दु निम्न हैं:–

(1) इस पैकेज में एम.एस.एम.ई.एस. क्षेत्र को महत्व दिया गया है। एम.एस.एम.ई.एस. क्षेत्र भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजन क्षेत्र है, इस कदम से श्रम गहन उद्योगों को बनाए रखने में मदद मिलेगी और इस तरह भारत के तुलनात्मक लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

(2) इसके अलावा, हथियारों के आयात को सीमित करने और रक्षा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को 49 प्रतिशत् से बढ़ाकर 74 प्रतिशत् करने से भारत के विशाल रक्षा आयात बिल को कम करते हुए आयुध निर्माण बोर्ड में उत्पादन को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।

 Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 13 June 2020

(स) तृतीयक क्षेत्रः– सरकार ने सभी क्षेत्रों में चिंताओं को दूर करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। इस क्षेत्र के प्रमुख बिन्दु निम्न हैंः–

(1) डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा के लिए मल्टी–मोड एक्सेस के लिए नया लॉन्च किया गया पीएम ई–विद्या कार्यक्रम पूरे राष्ट्र के लिए एक समान शिक्षण मंच प्रदान करता है, जो स्कूलों और विश्वविद्यालयों को शिक्षण घंटे के नुकसान के बिना ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को स्ट्रीम करने में सक्षम करेगा।

(2) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों को तैयार करने और ग्रास रूट वाले स्वास्थ्य संस्थानों में निवेश करके स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाया जाएगा।

(3) इसके अलावा, विदेशी बाजारों को उधार लेना मुश्किल है, क्योंकि डॉलर के संबंध में रुपया सभी समय कम रहने की संभावना अधिक है।

देश में कोरोना महामारी से लॉकडाउन के कारण नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें व कपड़े धोने की दुकानें, रेहड़ी–पटरी वालों की आजीविका पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इस समस्या को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक नई योजना पीएम स्वनिधि योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालो को सरकार द्वारा 10000 रूपये का लोन मुहैया कराया जायेगा इस योजना के अंतर्गत ये अल्पकालिक सहायता रु 10,000 छोटे सड़क विक्रेताओं को अपना काम फिर से शुरू करने में सक्षम बनाएंगे। इस योजना के जरिये आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी और भारत की अर्थव्यवस्था पर पटरी पर पुनः दौड़ने लगेगी।

इस योजना अथवा अभियान का उद्देश्य 130 करोड़ भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि देश का हर नागरिक संकट की इस घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चल सके और कोविड–19 की महामारी को हराने में अपना योगदान दे सके। समृद्ध और संपन्न भारत के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत अभियान निश्चित ही महत्वपूर्ण योगदान देगा, प्रधानमंत्री आर्थिक राहत पैकेज में सभी सेक्टरों की दक्षता बढ़ेगी और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। इस योजना के जरिये देश की अर्थव्यवस्था को 20 लाख करोड़ रूपये की सहायता राशि का संबल मिलेगा।

हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत देश को योजना के माध्यम से और मजबूत बनाने के लिए एक नयी घोषणा की है जिससे कोरोना वायरस की वजह से देश की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ गयी है उन्हें सुधारा जा सके और देश के लोगो को आत्मनिर्भर बनाया जा सके । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.)की सालाना बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में पीएम मोदी जी ने कहा है कि हमारी सरकार प्राइवेट सेक्टर को देश की विकास यात्रा में साझीदार मानती है भारत को फिर से तेज विकास के पथ पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी हैं , वो हैं – इंटेंट यानी इरादा, इन्क्लूजन यानी समावेशन, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा, इनोवेशन यानी नवोन्मेष। वास्तव में इन पर कार्य करने से हमारी अर्थव्यवस्था में निश्चित ही सुधार होगा। कोविड–19 ने देश और देश दुनिया के सामने बहुत से संकट खड़े किए हैं और चुनौती के समय में देश को अग्रसर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु, मध्यम वर्गीय गृह उद्योग)के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान एक रामबाण उपाय वर्तमान में सि) हो रहा है।   इस अभियान में एमएसएमई को महत्वपूर्ण बताया गया है। एमएसएमई जोकि 12 हजार करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के लाभार्थी देश में निवासरत सभी निवासी हैं अर्थात देश का गरीब नागरिक, श्रमिक, प्रवासी मजदूर, पशुपालक,मछुआरे, किसान, संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति, काश्तकार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यमवर्गीय उद्योग आदि सभी पात्रता अनुसार हैं और होगें। दिनांक 14 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मुख्यतः सभी वर्ग के लिए उपर्युक्त के अलावा प्रमुख निम्न घोषणाएं की गई जिससे सभी वर्ग लाभांवित हो रहे हैंः–

(1) कृषि अवसंरचना की स्थापना के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का कोष का निर्माण कृषकों को लाभ दिला रहा है।

(2) प्रधान मंत्री मातृ संपदा योजना के तहत मछुआरों के लिए 2000 करोड़ रुपये आवंटन का प्रावधान एक सराहनीय पहल है।

(3) 500 करोड़ रुपये के सभी फलों और सब्जियों को कवर करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार किया जाएगा।

(4) अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू जैसे आवश्यक भोजन में संशोधन लाया जाना एक अच्छा कदम है।

(5) कृषि विपणन सुधारों को एक नए कानून के माध्यम से लागू किया जाएगा जो अंतर्राज्यीय व्यापार की बाधाओं को दूर करेगा।

(6) किसान को सुविधात्मक कृषि उपज के माध्यम से मूल्य और गुणवत्ता आश्वासन दिया जाएगा।

(7) इस पैकेज से 10 करोड़ मजदूरों को लाभ के साथ–साथ एम.एस.एम.ई.से जुड़े 11 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा।

Copyright @ 2020 Authors

(8) देश के उद्योग क्षेत्र या इंडस्ट्री से जुड़े 3.8 करोड़ एवं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े 4.5 करोड़ कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा।
(9) ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु–मंझोले उद्योग, हमारे एम.एस.एम.ई.के लिए है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन बन रहा है।
(10) इस आर्थिक पैकेज से गरीब मजदूरों, कर्मचारियों के साथ ही होटल तथा टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को फायदा हो रहा है।
(11) देश के सड़क विक्रेताओं को सुविधा होने की अधिक संभावना है।
(12) इस पैकेज में कृषि क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचे, क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण आर्थिक उपायों की घोषणा की। इन निधियों के साथ अन्य उपाय जैसे शासन और प्रशासनिक सुधार भी सूची में शामिल हैं।
(13) भारत सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में प्रासंगिक संशोधन करने सहित कृषि क्षेत्रों में कानूनी ढांचे पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार केंद्रीय कानून के माध्यम से किसानों के विपणन विकल्पों को बढ़ाने के लिए कृषि विपणन सुधार लाएगी। यह किसानों को पारदर्शी तरीके से, खुले बाजारों, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों में अपने व्यवसाय का विस्तार करने में मदद करेगा।
(14) देश के स्वास्थ्य और शैक्षिक विभागों के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था का प्रावधान इस पैकेज में है।
15) देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष बल मिल रहा है।
(16) देश के सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियां में सुधार की पहल की गई है।
(17) आत्मनिर्भर भारत पैकेज में राज्य सरकारों के लिए निधि का भी प्रावधान है। सरकार ने आपातकालीन उद्देश्यों के लिए हर राज्य सरकार की अग्रिम सीमा में 60 प्रतिशत् की वृद्धि की है। कोविड–19 गतिविधियों के लिए राज्य सरकार के पक्ष में स्वास्थ्य मंत्रालय से 4,113 करोड़ रुपये का फंड जारी की बात की है।
(18)देश के रिजर्व बैंक ने मुद्रा कोष और नीतियों में भी परिवर्तन किया ताकि आम नागरिक को इस महामारी के समय राहत मिल सके।

आत्म निर्भर भारत अभियान का महत्त्व

आत्म निर्भर भारत अभियान में मुख्य बल स्थानीय मांग और आपूर्ति पर दिया गया है. इसके अंतर्गत छोटे–मंझोले उद्यमियों और रेहड़ी वालों, फेरी वालों जैसे असंगठित क्षेत्र के व्यवसायियों को आर्थिक संबल देने का प्रावधान किया जा रहा है। यह अनुभव किया गया कि संकट की स्थिति में स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ ही देश को बचाती हैं और उसे सशक्त बनाती हैं। जन साधारण से आह्वान किया जा रहा है कि वे स्थानीय वस्तुओं का क्रय करते हुए उन्हें बढ़ावा दें और प्रचार–प्रसार के माध्यम से उनको इतनी प्रसिद्धि दें कि स्थानीय उत्पाद नामी ब्रांड में बदल जाए और मान्यनीय मोदी जी "लोकल पर वोकल" थीम सफल हो जाये, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार संभवतः नजर आयेगा। हम सभी जानते है कि कोरोना संकट इतना बड़ा है कि बड़ी सी बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हिल गई हैं। इसमें सुधार के उपाय जारी हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत आर्थिक पैकेज का ध्यान इस बात पर है कि कैसे कर्मचारियों और कम्पनियों के हाथ में अधिक से अधिक पैसे आयें जिससे वे अधिक खर्चा कर सकें और अर्थव्यवस्था की गाड़ी फिर से पटरी पर आ सके।

आत्मनिर्भर भारत अभियान में सामाजिक, संस्कृति, शिक्षा और प्रौद्योगिकी की भूमिका

आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए समाज के प्रत्यैक वर्ग की भूमिका है और रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी सक्षमता के अनुसार यदि इस अभियान का प्रचार प्रसार कर एवं पात्रता अनुसार पात्र अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ दिलाता है तो निश्चित ही हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से शीघ्र जीत सकता है। परिणामस्वरूप हमारी संस्कृति और शिक्षा का तो एक ओर विकास होगा इसके साथ ही प्रौद्योगिकी का भी विकास होगा। प्रोद्योगिकी भी इस अभियान को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। समाज के सभी वर्गों से पात्र नागरिकों तक इस योजना का प्रचार प्रसार कर उनकों लाभ दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाने की अपेक्षा की जा रही है। वर्तमान में इसकी विशेषताएं एवं शर्तें लाभ आदि का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित कर इसको और भी अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। ताकि कोरोना जैसी महामारी से प्रभावित लोगों को फायदा मिल सके और हमारी अर्थव्यवस्था पुनः तेज गति से बढ़ने लगे।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के संकल्प

कोरोनावायरस संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ देश को विकास के नए दौर में ले जाने के लिए देश के विभिन्न वर्गों को एक साथ जुडने की आवष्यकता है तब कहीं देश को विकास की यात्रा को एक नई गति प्रदान हो सकेगी। इस अभियान के अंतर्गत देश के मजदूर श्रमिक किसान लघु उद्योग कुटीर उद्योग मध्यमवर्गीय उद्योग सभी पर

 Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 13 June 2020

विशेष ध्यान अथवा बल दिया जाएगा। यह पैकेज इन सभी उद्योगों को 20 लाख करोड़ की सहायता प्रदान करेगा जो कि भारत के एक गरीब नागरिक की आजीविका का साधन है। यह पीएम मोदी राहत पैकेज देश के हर श्रमिक व्यक्ति के लिए है जो हर स्थिति में देशवासियों के लिए परीक्षण करता है और देश को ऊँची बुलंदी की ओर अग्रसर करता है। कहा जा रहा है कि यह आर्थिक पैकेज सकल घरेलू उत्पाद(जी.एड़.पी.) के 10 प्रतिशत् के समतुल्य होगा यानी भारत 20 लाख करोड़ रू का आर्थिक पैकेज देने जा रहा है जिससे सूक्ष्म–लघु–मध्यम (एम.एस.एम.ई.) उद्योग को बढ़ावा मिले. यह एक राहत पैकेज होगा जो भारत के हर वर्ग के लिए उपलब्ध होकर आर्थिक विकास में साधक होगा।

निष्कर्ष

कोविड–19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए, हमारे प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को लॉकडाउन स्थितियों पर नए नियमों और आर्थिक राहत पैकेजों के साथ संबोधित किया है। भारत में इस महामारी के दुष्परिणामों पर लगाम लगाने के लिए अलग–अलग क्षेत्रों के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन आर्थिक पैकेज अत्मनिर्भार भारत अभियान के तहत आवंटित किया गया है। कोविड –19 महामारी या आपदा की स्थिति से पहले, केंद्र सरकार ने पहले ही देश के सामाजिक–आर्थिक गरीब और वंचित नागरिकों के लिए एक राहत कोष की घोषणा की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के एक हिस्से के रूप में 1,92,800 करोड़ रुपये का एक कोष सरकार द्वारा इन गरीब लोगों को पर्याप्त भोजन और अनाज प्रदान करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

लॉकडाउन से बाहर निकलने वाले देश के लिए आर्थिक पैकेज के लिए अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इस पैकेज को न्यायोचित तरीके से ग्रीनफिल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा सकता है। अधोसंरचना का खर्च विशिष्ट रूप से ऐसी संरचनाएं बनाता है जो उत्पादकता बढ़ाती हैं और लॉकडाउन से प्रभावित आबादी के वर्ग तक खर्च करने की शक्ति का विस्तार करती हैं, जिसका अर्थ है दैनिक मजदूर को रोजगार पाया जाना जो कारगर होगा। कोविड–19 से हमारी अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हुई और हो रही है। इस पैकेज में वित्तपोषण के लिए, भारत के विदेशी भंडार एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर खड़े हैं, जो रणनीतिक रूप से इसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पैकेज को विभिन्न क्षेत्रों के सुधार में प्रयुक्त कर सरकार और अधिक उपयोगी बना सकती है जो जो ट्रिकल डाउन प्रभाव को प्रोत्साहित करेगा। कोविड–19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट पर आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के न्यायोचित परिपालन से हम अतिशीघ्र इस आपदा से लडकर जीत सकते हैं और कोविड–19 के युग के बाद अभूतपूर्व अवसरों की शुरूआत हो सकती है जो अर्थव्यवस्था को सुधार रूपी मल्हम जैसी काम करेगी।

हम सभी लोग जानते है कि कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था की गति स्थिर हो गई है। पर सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान ने इसमें संचार ला रही है। केंद्र सरकार के इस पैकेज से भारत देश एक नई ऊचाई की तरफ जायेगा। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि यह एक आर्थिक पैकेज है जो भारत के हर वर्ग के लिए उपलब्ध होगा। अतः आशा है हम सभी इस अभियान को सफल बनाने के लिए यथासंभव प्रयास करेगें तब कहीं जाकर कोरोना से प्रभावित होने के वावजूद अर्थव्यवस्था पटरी पर दौड़गी और विश्व में एक उदाहरण बनेगी। यही अपेक्षा हमारी और हमारे आलेख है।

000000
0000
00

स्त्रोत :–

1 परीक्षा मंथन जनसंख्या एवं नगरीकरण (अतिरिक्तांक जनगणना 2011) ताशकंद मार्ग इलाहाबाद आई. एस. बी. एन. नं 978–81–921695–9–0 पेज नं. 3
2 भारतीय अर्थव्यवस्था 2019–20 शिव कुमार ओझा, अर्चना ओझा बौद्विक प्रकाशन प्रयागराज उ.प्र. पेज न. 9
3 प्रतियोगिता दर्पण जून–जुलाई 2020 आगरा पेज नं. 72
4 प्रतियोगिता दर्पण जून–जुलाई 2020 आगरा पेज नं. 72
5 प्रतियोगिता दर्पण जून–जुलाई 2020 आगरा पेज नं. 72
6 प्रतियोगिता दर्पण जून–जुलाई 2020 आगरा पेज नं. 78
7 https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-editorials/atma-nirbhar-bharat-abhiyan-challenges

Copyright @ 2020 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-10 Issue-6 No. 13 June 2020

मौलिकता का प्रमाण–पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि यह मेरा मौलिक एवं अप्रकाशित षोधपत्र है जिसके निर्माण में हमने ऊपरलिखित आदि स्त्रोंतों का सहयोग लिया है ।

डॉ. असलम खॉन सहा. प्राध्यापक (अर्थषास्त्र)
षासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय दमोह (म.प्र.)
मे. न. 9406930786
draslamkhan3179@gmail.com

Copyright @ 2020 Authors